NITIN SIR CLASSES

THE HINDU
INDIA'S NATIONAL NEWSPAPER SINCE 1878

□□□□□□ □□□□□□□

The Hindu Important News Articles & Editorial For UPSC CSE

Monday, 03 Nov , 2025

Edition : International Table of Contents

Page 01 **Syllabus : GS 3 : Science and Tech / Prelims**	इसरो ने भारत के सबसे भारी संचार उपग्रह जीसैट-7आर का प्रक्षेपण किया
Page 06 **Syllabus : GS 2 : Indian Polity / Prelims**	मध्य प्रदेश को छोड़कर लेह में अब कोई निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं है
Page 08 **Syllabus : GS 2 : International Relations / Prelims**	तालिबान को शामिल करें, उन्हें न पहचानें
Page 11 **Syllabus : GS 3 : Science and Tech**	क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म धीमी गति से मर रहे हैं?
Page 13 **Syllabus : GS 1 : Social Issues / Prelims /**	वैश्विक जहाजों पर भारतीय महिला शक्ति में वृद्धि
Page 08 : Editorial Analysis **Syllabus : GS 2 : Indian Polity**	आदर्श युवा ग्राम सभाओं का दृष्टिकोण

Page 01 : GS 3 : Science and Tech / Prelims

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने श्रीहरिकोटा से एलवीएम 3-एम 5 पर भारत के सबसे भारी स्वदेशी रूप से निर्मित संचार उपग्रह जीसैट-7आर (सीएमएस-03) का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया । भारतीय नौसेना की संचार और निगरानी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया यह मिशन भारत की रक्षा और अंतरिक्ष आत्मनिर्भरता में एक महत्वपूर्ण छलांग का प्रतीक है।

ISRO launches advanced GSAT-7R, India's heaviest communication satellite

Saurabh Trivedi
Vasudevan Mukunth
NEW DELHI/CHENNAI

The Indian Space Research Organisation on Sunday successfully launched the Indian Navy's advanced communication satellite GSAT-7R (CMS-03) from the Satish Dhawan Space Centre in Sriharikota.

The indigenously designed and developed satellite, weighing approximately 4,400 kg, is India's heaviest communication satellite to date and marks a major milestone in strengthening the Navy's space-based communications and maritime domain awareness.

The ISRO launched the rocket aboard its most powerful launch vehicle, the LVM3, on its M5 mission. The lift-off took place at about 5.26 p.m. from the second launch pad, and mission control soon confirmed that the satellite had been successfully inserted into a geosynchronous transfer orbit (GTO).

This is the heaviest Indian-built communications satellite launched from Indian soil so far. Because of the high mass of the GSAT-7R, the launch vehicle targeted a standard GTO; once there, the satellite will raise and circularise its orbit using its on-board propulsion systems.

LVM3-M5 lifts off carrying the GSAT-7R communication satellite from Satish Dhawan Space Centre in Sriharikota on Sunday. X/@ISRO

Boost to self-reliance

The Navy said that equipped with state-of-the-art indigenous components, the GSAT-7R would provide robust and secure telecommunication coverage across the Indian Ocean Region. Its advanced payload features transponders supporting voice, data, and video links over multiple communication bands, ensuring seamless connectivity between the Navy's ships, submarines, aircraft, and Maritime Operations Centres.

The launch highlights India's growing self-reliance in space technology and the Navy's commitment to safeguarding national maritime interests, it said.

It stands as a testament to Aatmanirbhar Bharat, enabling the armed forces to operate with enhanced situational awareness and secure, high-capacity communication links in complex maritime environments, it added.

The launch also demonstrated the capacity of the LVM3 rocket to routinely handle four-tonne-plus satellites to GTO from India, reducing dependence on foreign launchers for heavy communications satellites as well as feeding directly into ISRO's preparations for Gaganyaan, its maiden human spaceflight programme, which plans to use an evolved LVM3 variant.

"ISRO has successfully launched the heaviest GEO communication satellite from Indian soil," ISRO Chairman V. Narayanan posted on X following the successful launch. "The Indian space sector is soaring high to provide valuable services to the user community in and around the Indian region," he added.

मुख्य विश्लेषण

एक.**तकनीकी महत्व**

- करीब 4,400 किलोग्राम वजनी जीसैट-7आर भारतीय धरती से प्रक्षेपित किया गया सबसे भारी संचार उपग्रह है।
- यह एलवीएम 3 की चार टन से अधिक पेलोड को जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट (जीटीओ) में संभालने की सिद्ध क्षमता को प्रदर्शित करता है, जो विदेशी सहायता के बिना भारी-लिफ्ट लॉन्च के लिए भारत की क्षमता को मजबूत करता है।
- उपग्रह के उन्नत पेलोड में नौसेना संचालन के लिए सुरक्षित आवाज, डेटा और वीडियो लिंक का समर्थन करने वाले मल्टी-बैंड ट्रांसपोंडर शामिल हैं।

दो. **रणनीतिक और सुरक्षा आयाम**

- जीसैट-7आर, जीसैट-7 श्रृंखला का हिस्सा है, जो क्रमशः नौसेना और वायु सेना की सेवा करते हैं।
- यह हिंद महासागर क्षेत्र में जहाजों, पनडुब्बियों, विमानों और समुद्री संचालन केंद्रों के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाते हुए नेटवर्क-केंद्रित युद्ध को मजबूत करेगा।
- यह प्रणाली समुद्री क्षेत्र जागरूकता (एमडीए) को बढ़ाती है – जो हिंद-प्रशांत क्षेत्र में बढ़ती रणनीतिक प्रतिस्पर्धा के बीच महत्वपूर्ण है।

तीन.**आत्मनिर्भरता और आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा**

- यह मिशन उपग्रह डिजाइन, पेलोड विकास और लॉन्च बुनियादी ढांचे में भारत की स्वदेशी क्षमता को रेखांकित करता है।
- यह विदेशी लॉन्च वाहनों पर निर्भरता को कम करता है और अंतरिक्ष और रक्षा क्षेत्रों में 'आत्मनिर्भर भारत' दृष्टिकोण का समर्थन करता है।
- एलवीएम 3 का प्रदर्शन सीधे इसरो के गगनयान कार्यक्रम में भी शामिल है, जो भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन है।

चार.**आर्थिक और संस्थागत प्रभाव**

- यह मिशन भारत की दोहरे उपयोग वाली अंतरिक्ष संपत्तियों को मजबूत करता है – नागरिक और रक्षा दोनों अनुप्रयोगों को बढ़ावा देता है।
- यह इसरो और सशस्त्र बलों के बीच बढ़ते तालमेल के साथ-साथ सार्वजनिक और निजी कंपनियों को शामिल करते हुए एक आत्मनिर्भर अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र की ओर भारत के परिवर्तन को दर्शाता है।

निष्कर्ष

जीसैट-7आर का सफल प्रक्षेपण रणनीतिक स्वायत्तता और तकनीकी प्रगति की दिशा में भारत के मार्च में एक मील का पत्थर है। समुद्री संचार, निगरानी और सुरक्षा को बढ़ाकर, यह एक विश्वसनीय क्षेत्रीय शक्ति और एक आत्मनिर्भर अंतरिक्ष यात्री राष्ट्र के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करता है। यह मिशन न केवल भारतीय नौसेना की परिचालन तत्परता को मजबूत करता है बल्कि राष्ट्रीय रक्षा और अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाओं का समर्थन करने में इसरो की बढ़ती भूमिका को भी प्रदर्शित करता है।

UPSC Prelims Practice Question

प्रश्न: जीसैट-7आर उपग्रह के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. जीसैट-7आर भारत का पहला संचार उपग्रह है जिसे विशेष रूप से भारतीय सेना के लिए डिज़ाइन किया गया है।

2. इसे श्रीहरिकोटा से LVM3 लॉन्च व्हीकल पर लॉन्च किया गया था।

3. यह उपग्रह भारतीय नौसेना के लिए समुद्री संचार और निगरानी को बढ़ाएगा।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3

(d) 1, 2 और 3

उत्तर: b)

UPSC Mains Practice Question

प्रश्न: जीसैट-7आर का प्रक्षेपण रक्षा और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता की भारत की खोज में एक मील का पत्थर है। भारत की समुद्री सुरक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता के लिए इस मिशन के महत्व पर चर्चा करें। **(150 शब्द)**

Page 06 : GS 2 : Indian Polity / Prelims

लद्दाख का लेह जिला राजनीतिक रूप से संवेदनशील चरण में प्रवेश कर गया है क्योंकि लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद (एलएएचडीसी), लेह का पांच साल का कार्यकाल 31 अक्टूबर, 2025 को समाप्त हो गया है। अभी तक किसी नए चुनाव की घोषणा नहीं होने के कारण, इस क्षेत्र में वर्तमान में कोई निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं है, इसके एकमात्र सांसद मोहम्मद हनीफा को छोड़कर। चुनावों में देरी लद्दाख की संवैधानिक और प्रशासनिक स्थिति को लेकर नागरिक समाज समूहों और केंद्र सरकार के बीच चल रही बातचीत से जुड़ी हुई है।

पृष्ठभूमि और संदर्भ

THE HINDU
INDIA'S NATIONAL NEWSPAPER SINCE 1878

2019 में जम्मू-कश्मीर के विभाजन के बाद, लद्दाख को विधानसभा के बिना केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) बना दिया गया था। इस क्षेत्र में शासन मुख्य रूप से दो स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषदों के माध्यम से किया जाता है – लेह और कारगिल में एक-एक – एलएएचडीसी अधिनियम, 1997 के तहत गठित किया गया है।

एलएएचडीसी, लेह, 40 कार्यात्मक क्षेत्रों में विकास गतिविधियों की योजना बनाने और उन्हें क्रियान्वित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसमें पार्षदों को व्यक्तिगत विकास निधि प्राप्त होती है। इसलिए, परिषद की अनुपस्थिति एक प्रशासनिक शून्य पैदा करती है, विशेष रूप से दूरदराज और सीमावर्ती क्षेत्रों में जहां उच्च अधिकारियों तक पहुंच सीमित है।

Barring MP, Leh now has no elected representatives

The five-year term of the hill council came to an end on October 31 and fresh elections may be held only after talks between civil society groups and Union Home Ministry take a decisive turn

Vijaita Singh
NEW DELHI

As Leh district in Ladakh ceases to have any elected representatives from October 31, with the five-year term of the hill council coming to an end, elections to the local body are likely to be held only after ongoing talks between civil society groups and the Centre take a decisive turn, officials said. Ladakh MP Mohammad Haneefa is now its only representative.

Delay in election: The election to the 30-member LAHDC, Leh was last held in 2020 . FILE PHOTO

On October 22, a month after after four people were killed in police action against protesters seeking Statehood, the civil society groups Leh Apex Body (LAB) and Kargil Democratic Alliance (KDA) – representing the two districts in Ladakh – resumed talks on the region's status with the Ministry of Home Affairs (MHA).

The groups were asked by the government to prepare a draft framework, including a road map for constitutional safeguards for Ladakh. Though dates for the next meeting are yet to be announced, the LAB and KDA have taken the help of legal experts to argue for their existing demands, including inclusion under the Sixth Schedule of the Constitution (tribal status) and Statehood, members of the groups said. "The LAB and KDA are drafting their suggestions and would share notes to present a common proposal," said Sajjad Kargili of the KDA.

Special provisions

At the October 22 meeting, Ministry officials indicated to the two groups that special provisions guaranteed under Article 371 of the Constitution can be considered for Ladakh.

On October 31, an order by the Ladakh administration cited ongoing process for creation of new districts and the consequent need for redrawing boundaries of council areas and constituencies, for the delay in holding elections. Besides, it also highlighted the need for implementation of the amendment to the Ladakh Autonomous Hill Development Councils (LAHDC) Act, 1997, providing one-third reservation for women in the LAHDCs, and said "holding elections to constitute a new LAHDC, Leh, is not practicable at this stage, as it would lead to representational anomalies and administrative inconsistencies".

The order delegated the hill council's functions to the Deputy Commissioner "until a new council is constituted following fresh elections".

The new districts were announced in 2024 and women's reservation was notified on June 3 this year.

Detrimental effect

Konchok Stanzin, former councillor of Chushul along China border, said barring an MP, there were no public representatives in Leh. "This is particularly detrimental for people living in the regions bordering China. If they have an issue, they will have to come to the district headquarters in Leh city, hundreds of kilometres away. Most people do not have the resources for that. As a councillor, I used to take care of their demands pertaining to connectivity, education, health, and livelihood, among others," Mr. Stanzin told *The Hindu*.

He said the hill council is empowered to take decisions on 40 functions and each councillor has a development fund of ₹1.5 crore.

The election to the 30-member LAHDC, Leh was last held in 2020, with the BJP winning 15 seats and the Congress nine. Four councillors are nominated by the Lieutenant-Governor. The LAHDC for Kargil district was constituted in 2023 and its term will come to an end in 2028.

For 2025-26, the Leh hill council was allocated ₹255 crore by the MHA.

वर्तमान मुद्दा

एलएएचडीसी के नए चुनाव कराने में देरी दो मुख्य कारणों से उपजी है:

एक. लद्दाख के संवैधानिक सुरक्षा उपायों के संबंध में गृह मंत्रालय (एमएचए) के साथ लेह एपेक्स बॉडी (एलएबी) और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (केडीए) के बीच बातचीत चल रही है।

दो. जिलों का पुनर्गठन और एलएएचडीसी अधिनियम में हालिया संशोधन में महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण अनिवार्य है, जिसके लिए चुनाव होने से पहले सीमाओं को फिर से तैयार करने की आवश्यकता है।

जब तक चुनाव नहीं हो जाते, लेह के उपायुक्त परिषद के कार्यों को पूरा करेंगे – एक ऐसा कदम जो जमीनी स्तर पर लोकतंत्र के कमजोर होने पर चिंता पैदा करता है।

मांगें और बातचीत

नागरिक समाज समूह (एलएबी और केडीए) मांग रहे हैं:

- लद्दाख को राज्य का दर्जा
- संविधान की छठी अनुसूची के तहत शामिल करना (आदिवासी दर्जा और स्थानीय स्वायत्तता प्रदान करना)
- अनुच्छेद 371 के तहत संरक्षण (कुछ राज्यों/क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान)

22 अक्टूबर की बैठक में, गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने संकेत दिया कि छठी अनुसूची को शामिल करने के विकल्प के रूप में अनुच्छेद 371 प्रकार के प्रावधानों का पता लगाया जा सकता है। समूह वर्तमान में केंद्र के समक्ष एक एकीकृत प्रस्ताव पेश करने के लिए कानूनी विशेषज्ञों के साथ एक संयुक्त मसौदा ढांचा तैयार कर रहे हैं।

प्रभाव

- शासन वैक्यूम: निर्वाचित पार्षदों की अनुपस्थिति स्थानीय प्रतिनिधित्व को कमजोर करती है, खासकर चीन के पास चुशुल जैसे सीमावर्ती क्षेत्रों में।
- प्रशासनिक चुनौतियां: पार्षदों के बिना, नागरिकों को स्थानीय मुद्दों को संबोधित करने के लिए जिला मुख्यालय पर भरोसा करना चाहिए, भागीदारी शासन को कमजोर करना चाहिए।
- सुरक्षा और रणनीतिक प्रभाव: चीन के साथ लद्दाख की संवेदनशील सीमा को देखते हुए, स्थिरता और जनता के विश्वास को बनाए रखने के लिए प्रभावी स्थानीय शासन महत्वपूर्ण है।
- राजनीतिक संवेदनशीलता: लंबे समय तक अनिश्चितता स्थानीय असंतोष को बढ़ावा दे सकती है, खासकर अगर संवैधानिक सुरक्षा उपायों में देरी हो या कम हो जाए।

निष्कर्ष

एलएएचडीसी लेह का कार्यकाल बिना किसी उत्तराधिकारी परिषद के समाप्त होना 2019 के बाद लद्दाख में चल रहे राजनीतिक प्रवाह को उजागर करता है। जबकि संवैधानिक सुरक्षा उपायों पर स्थानीय निकायों के साथ केंद्र का जुड़ाव एक सकारात्मक कदम है, देरी से चुनावों से लोकतांत्रिक जवाबदेही कमजोर होने और स्थानीय समुदायों को अलग-थलग करने का जोखिम है। आगे बढ़ते हुए, लद्दाख में समावेशी शासन और क्षेत्रीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए समय पर चुनाव और सार्थक स्वायत्तता के साथ प्रशासनिक पुनर्गठन को संतुलित करना महत्वपूर्ण होगा।

UPSC Prelims Practice Question

प्रश्न: लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद (एलएएचडीसी) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. इसका गठन 2019 में जम्मू और कश्मीर के विभाजन के बाद पारित एक केंद्रीय अधिनियम के तहत किया गया था।

2. इसे संविधान की राज्य सूची के तहत सूचीबद्ध विषयों पर कानून बनाने की शक्ति है।

3. एलएएचडीसी में प्रत्येक पार्षद को एक विकास निधि आवंटित की जाती है और वह जिला स्तरीय योजना और कार्यान्वयन में भाग लेता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 2 और 3

(c) केवल 3

(d) 1, 2 और 3

उत्तर: c)

UPSC Mains Practice Question

प्रश्न: लद्दाख के लिए छठी अनुसूची के दर्जे और राज्य के दर्जे की मांग भारत के सीमांत क्षेत्रों में सांस्कृतिक संरक्षण और राजनीतिक प्रतिनिधित्व की गहरी चिंताओं को दर्शाती है। **(150 शब्द)**

Page 08 : GS 2 : International Relations / Prelims

अगस्त 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता में वापसी ने दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण भू-राजनीतिक बदलाव को चिह्नित किया। भारत के लिए, जिसने अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में $ 3 बिलियन से अधिक का निवेश किया था और पिछली शासन के तहत मजबूत सद्भावना का आनंद लिया था, इस विकास ने एक रणनीतिक दुविधा पैदा कर दी: तालिबान के साथ जुड़ना है या उन्हें अलग-थलग करना है। जैसे-जैसे पाकिस्तान और तालिबान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है, भारत के दृष्टिकोण पर बहस ने नए सिरे से ध्यान आकर्षित किया है।

Engage the Taliban, don't recognise them

Stanly Johny

As the saying goes, the enemy's enemy is a friend. When the Afghan Taliban were an insurgency, they were clients of the Pakistani military establishment. Now, they are the state in Afghanistan. Their return to power in Kabul also brought back old fissures between Pakistan and Afghanistan, two neighbours divided by a disputed 2,640-kilometre border, to the centre of inter-state relations. As tensions between the two rise, often spilling into cross-border clashes, India may be tempted to see the Taliban, its enemy's enemy, as a 'friend'.

It may not be a coincidence that Pakistan bombed Kabul earlier in October, just as Taliban Foreign Minister Amir Khan Muttaqi was visiting India. Mr. Muttaqi's visit, the highest-level contact between the Sunni extremist Taliban and India, was the clearest indication yet that both sides are keen to improve ties. India has since decided to upgrade its technical mission in Kabul to a full embassy and resume stalled infrastructure and welfare projects with Mr. Muttaqi giving his assurance that the Taliban regime "will not allow any group to use our territory against others".

The case for engagement is well known. When the Taliban, then backed by Pakistan, returned to Kabul in August 2021, India, which had backed anti-Taliban forces in the 1990s, faced the prospect of losing the influence it had built in Afghanistan over the previous two decades. The question before New Delhi was whether to remain engaged with the new rulers or distance itself from them.

India's objectives

Broadly speaking, India has three objectives when it comes to dealing with Afghanistan. First, it had invested some $3 billion in Afghanistan between 2001 and 2021 – after the collapse of the first Taliban regime. It seeks to protect those investments, and build on the goodwill it earned during the period. Second, unlike in the 1990s, New Delhi does not want Afghan soil to be used by anti-India militants. Third, it does not want the Taliban to become an external arm of Pakistan's establishment, which would give Islamabad-Rawalpindi strategic depth in the region. As an Indian diplomat told this writer in 2021, soon after the Taliban's reconquest, "India would like to explore the autonomy of the Taliban from their masters". To meet these goals, India has opted for a policy of conditional and gradual engagement with Taliban 2.0.

Mr. Muttaqi's visit to New Delhi and the decision to upgrade the Indian mission in Kabul to an embassy suggest that India is expanding the scope of this conditional engagement. The dramatic deterioration in Pakistan-Taliban relations adds a new geopolitical dimension to India's approach. These developments have prompted calls for India to move faster in formally recognising the Taliban regime. There is, indeed, a case for recognition. The Taliban appear more consolidated than they were in the 1990s, and unlike in the past, no regional power seems interested in backing anti-Taliban forces – at least for now. The National Resistance Front, the primary anti-Taliban group, remains weak, with its leadership in exile in Tajikistan. The Taliban's most serious military challenge comes from the Islamic State-Khorasan, a transnational terrorist outfit that threatens regional security. Russia has formally recognised the Taliban, and China has exchanged ambassadors with Kabul.

Long-term risks

While recognition of the Taliban could allow India to fast-track cooperation with the regime, further deepening Pakistan's anxieties, it would also carry significant long-term risks. The Taliban, who emerged from the anarchy of the Afghan civil war in the early 1990s, have not fundamentally changed. Nor have they ever claimed to have changed – either ideologically or programmatically.

To be sure, the Taliban are not the only totalitarian regime in the world, and states, even democracies, should do diplomacy with different political systems. But the Taliban's totalitarianism is distinct. It is perhaps the only regime that bars girls from attending school beyond the primary level. It has enforced strict segregation between men and women in public spaces, and largely banned women from workplaces. The regime, headed by its reclusive Kandahar-based supreme leader Hibaitullah Akhundzada, and run by the Kabul Taliban, has maintained high levels of repression at a time when the economy is in serious trouble. Afghanistan's economy has contracted by around one-third since the Taliban seized power. Nearly 22.9 million Afghans – almost half the population – require humanitarian assistance this year. The exclusion of women from the workforce and education will have economic and social consequences. While the Taliban claim to have improved security over the past four years, they have also overseen a near-collapse of the economy.

Amid high-decibel repression and mounting economic distress, it is far from certain that the Pashtun, men-only regime of the Taliban has truly consolidated power in Afghanistan, a country of deep ethnic diversity that has seen almost continuous conflict since the mid-1970s. In the early 2000s, after the Taliban were toppled and the Islamic Republic was taking shape, Afghanistan enjoyed a period of relative calm and stability. Many believed that the country had embarked on a path towards democratisation and socio-economic modernisation. But it was only a matter of time before the Taliban re-emerged from the mountains of Pakistan's tribal belt to challenge the republic. So today's relative calm should not misguide anyone that the Taliban had won absolute lasting control over Afghanistan. It makes sense for India to adopt a wait-and-watch approach.

Deep networks

In their second stint, the Taliban have sought to project an image of having severed ties with transnational jihadist organisations. The Taliban learned a key lesson from 2001: it was not their repressive policies at home that led to their downfall but their open alliance with al-Qaeda. This time, they have adopted a more pragmatic posture. In public, their leaders insist that they will not allow transnational groups to use Afghan territory. Yet, this does not mean that the Taliban have genuinely severed ties with such groups. The Haqqani network, which has long maintained close ties with al-Qaeda, is now deeply integrated into the Taliban establishment.

According to a recent report by a United Nations Security Council monitoring group, the Taliban have allowed al-Qaeda to consolidate "through safe houses and training camps scattered across Afghanistan". It notes that the Taliban remain "the primary partner of all foreign terrorist groups operating in Afghanistan", including al-Qaeda, Pakistani Taliban, Jaish-e-Mohammad, Lashkar-e-Taiba and the Islamic Movement of Uzbekistan. The only exception is the Islamic State-Khorasan, which opposes Taliban rule. For now, these groups have been allowed to operate quietly without posing an immediate security threat to Afghanistan's neighbouring countries or the wider region. But if domestic pressures mount, and the Taliban's grip on power weakens, these networks could easily resurface, because they haven't given up their commitment to global jihadism. In that case, the enemy's enemy may well turn out to be India's enemy too.

If India recognises the Taliban regime and allows the so-called Islamic Emirate to take over its embassy in New Delhi, that would grant the Taliban legitimacy they have long sought. It would also strengthen the Taliban's regional standing and prompt more countries to do the same. But such a move would also shut one of the few remaining windows New Delhi can press the Taliban to reform. Rather than pursuing short-term realpolitik, India should adopt a long-term strategic approach. Faced with a hostile Pakistan across the border and a collapsing economy at home, the Taliban need India's assistance far more than India needs the Taliban. While engaging the regime, both bilaterally and through regional and international mechanisms, New Delhi must urge the group to respect at least the fundamental freedoms of the Afghan people. If India's interests lie in stability in Afghanistan, Afghanistan's stability will ultimately depend on economic recovery, political inclusion and regional integration – not on the Taliban's guns.

While engaging the regime, both bilaterally and through regional and international mechanisms, New Delhi must urge the group to respect at least the fundamental freedoms of the Afghan people

stanly.johny@thehindu.co.in

मुख्य विश्लेषण

अफगानिस्तान में भारत के रणनीतिक उद्देश्य

भारत की अफगानिस्तान नीति तीन प्रमुख उद्देश्यों द्वारा निर्देशित है:

एक. 2001-2021 के बीच निर्मित पिछले निवेशों और सद्भावना की रक्षा करना।

दो. जैश-ए-मोहम्मद या लश्कर-ए-तैयबा जैसे भारत विरोधी आतंकी संगठनों द्वारा अफगान धरती का इस्तेमाल होने से रोकना।
तीन. यह सुनिश्चित करना कि तालिबान पाकिस्तान का प्रॉक्सी न बने, जिससे भारत के क्षेत्रीय हितों को खतरा हो सकता है।

इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, नई दिल्ली ने एक सशर्त और कैलिब्रेटेड जुड़ाव का अनुसरण किया है – तालिबान नेतृत्व के शासन को वैध बनाए बिना उसके साथ संपर्क बनाए रखना।

क्षेत्रीय गतिशीलता को स्थानांतरित करना

सीमा पर झड़पों और अफगान क्षेत्र के अंदर इस्लामाबाद के हवाई हमलों सहित पाकिस्तान-तालिबान संबंधों में हालिया गिरावट ने भू-राजनीतिक संदर्भ को बदल दिया है। तालिबान के पाकिस्तान से स्वतंत्रता का दावा करने और भारत के साथ बेहतर संबंधों की मांग के साथ, नई दिल्ली को एक संभावित अवसर मिल रहा है। तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी की भारत यात्रा और भारत के काबुल मिशन को अपग्रेड करने का निर्णय एक गहरे जुड़ाव को दर्शाता है।

हालांकि, चीन और रूस जैसे देशों ने तालिबान के साथ राजदूतों को मान्यता दी है या उनका आदान-प्रदान किया है, लेकिन भारत ने औपचारिक मान्यता देने से परहेज किया है – दीर्घकालिक जोखिमों से अवगत है।

औपचारिक मान्यता के जोखिम

एक. वैचारिक कठोरता और दमन: तालिबान अपने कट्टरपंथी दृष्टिकोण में अपरिवर्तित रहता है, महिलाओं की शिक्षा, कार्य और सार्वजनिक उपस्थिति पर कठोर प्रतिबंध लागू करता है।
दो. आर्थिक पतन: 2021 के बाद से अफगानिस्तान की जीडीपी में एक तिहाई की गिरावट आई है; इसकी लगभग आधी आबादी को मानवीय सहायता की आवश्यकता है।
तीन. संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्टों के अनुसार, तालिबान अल-कायदा, जैश-ए-मोहम्मद और हक्कानी नेटवर्क जैसे चरमपंथी समूहों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखता है। अफगानिस्तान की धरती को आतंकवाद के लिए इस्तेमाल होने से रोकने का उनका वादा संदिग्ध बना हुआ है।
चार. झूठी स्थिरता: तालिबान का नियंत्रण समेकित दिखाई दे सकता है, लेकिन गहरे जातीय विभाजन, आर्थिक संकट और समावेशिता की कमी अफगानिस्तान की राजनीतिक स्थिरता को अनिश्चित बनाती है।

अब तालिबान को मान्यता देने से उनके सत्तावादी शासन को वैधता मिल जाएगी और सुधारों या समावेशी शासन को आगे बढ़ाने के लिए भारत का लाभ कम हो जाएगा।

सशर्त सगाई का मामला

मान्यता के बिना जुड़ाव भारत को रणनीतिक लचीलापन प्रदान करता है। संपर्क और मानवीय सहयोग बनाए रखकर, भारत निम्नलिखित कर सकता है:

- अफगानिस्तान में अपनी परियोजनाओं और प्रभाव की रक्षा करें।
- आतंकी गतिविधियों पर बारीकी से नजर रखें।
- सहायता और बुनियादी ढांचे के माध्यम से आम अफगानों के बीच सद्भावना का निर्माण करें।
- बुनियादी स्वतंत्रता के लिए संयम और प्रेस को प्रोत्साहित करने के लिए राजनयिक चैनलों का उपयोग करें।

□□□□□ □□□□□□□

जैसा कि स्टैनली जॉनी ने नोट किया है, तालिबान को भारत की उससे ज्यादा जरूरत है, जितना कि भारत की जरूरत है, उनके आर्थिक अलगाव और नाजुक वैधता को देखते हुए।

निष्कर्ष

भारत की अफगानिस्तान नीति को यथार्थवाद और सिद्धांत को संतुलित करना चाहिए। जबकि राष्ट्रीय हितों और क्षेत्रीय स्थिरता की रक्षा के लिए तालिबान को शामिल करना आवश्यक है, औपचारिक मान्यता भारत की नैतिक और कूटनीतिक स्थिति को कमजोर करेगी। नई दिल्ली को अफगानिस्तान में स्थिरता, आर्थिक सुधार और राजनीतिक समावेशन को बढ़ावा देने के लिए लाभ के रूप में जुड़ाव का उपयोग करते हुए अपने इंतजार करो और देखो दृष्टिकोण जारी रखना चाहिए । अंततः, अफगानिस्तान में स्थायी शांति तालिबान की बंदूकों पर नहीं, बल्कि क्षेत्र में सुधार और एकीकरण की उनकी इच्छा पर निर्भर करेगी।

UPSC Prelims Practice Question

अफगानिस्तान में तालिबान शासन के प्रति भारत की नीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. भारत ने काबुल में तालिबान सरकार को औपचारिक रूप से मान्यता दे दी है।

2. भारत ने काबुल में अपने दूतावास को फिर से खोल दिया है और कुछ मानवीय और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को फिर से शुरू किया है।

3. भारत की प्रमुख चिंताओं में से एक यह है कि अफगान धरती का उपयोग भारत विरोधी आतंकवादी गतिविधियों के लिए नहीं किया जाना चाहिए।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3

(d) 1, 2 और 3

उत्तर : b)

UPSC Mains Practice Question

प्रश्न : भारत को तालिबान के साथ बातचीत करनी चाहिए लेकिन उन्हें मान्यता नहीं देनी चाहिए। अफगानिस्तान में भारत के रणनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा हितों के आलोक में इस कथन पर चर्चा करें। **(250 शब्द)**

Page : 11 : GS 3 : Science and Tech / Prelims

डिजिटल युग में, सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म और ऑनलाइन सेवाएँ संचार, मनोरंजन और वाणिज्य का अभिन्न अंग बन गई हैं। हालाँकि, उपयोगकर्ताओं को तेजी से लग रहा है कि ये प्लेटफ़ॉर्म कम उपयोगकर्ता-अनुकूल और अधिक शोषक होते जा रहे हैं। इस घटना को कनाडाई लेखक और कार्यकर्ता कोरी डॉक्टरो द्वारा "enshittification" के रूप में वर्णित किया गया है - एक ऐसी प्रक्रिया जहां उपयोगकर्ताओं और रचनाकारों की कीमत पर निगमों द्वारा लाभ-अधिकतम व्यवहार के कारण डिजिटल प्लेटफॉर्म समय के साथ खराब हो जाते हैं।

मुख्य विश्लेषण

1. Enshittification को समझना

- परिभाषा: 2022 में कोरी डॉक्टरो द्वारा गढ़ा गया, एनशिटिफिकेशन ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के क्रमिक क्षरण को संदर्भित करता है क्योंकि वे उपयोगकर्ता अनुभव पर लाभ निष्कर्षण को प्राथमिकता देते हैं।
- प्रक्रिया:
  डॉक्टरो इस प्रक्रिया को तीन चरणों में समझाता है:
  एक. प्लेटफ़ॉर्म शुरू में उपयोगकर्ताओं को आकर्षित करने के लिए अच्छे होते हैं।
  दो. फिर वे व्यावसायिक ग्राहकों (विज्ञापनदाताओं, विक्रेताओं) के लाभ के लिए उपयोगकर्ताओं का शोषण करते हैं।
  तीन. अंत में, वे अपने स्वयं के लाभ को अधिकतम करने के लिए व्यावसायिक ग्राहकों का शोषण करते हैं - जिससे पतन होता है।

Are social media platforms dying a slow death?

'Enshittification' is a term used to describe how digital experiences and services have become worse over time. However, the word's creator says this is a deliberate process, and that pushing back is possible

Sahana Venugopal

Not too many years ago, you could watch endless YouTube videos with ease, but now you must sit through unskippable ads to access the content you want – unless you pay. Twitter used to be a space to collect news, engage with verified figures, and discuss world events, but is now teeming with verified scammers. Instagram was once an app to post and admire photos, but it now prioritises scrolling through viral and commercial short videos chosen by an algorithm. Google helped you find articles of repute and academic papers for projects, but now serves up an AI-generated mishmash of content that you will have to further vet. What has caused this degradation across platforms and apps? One theory that has gained traction is enshittification.

What is enshittification?

In 2022, the Canada-born author, tech journalist, and activist Cory Doctorow coined the term "enshittification." The now-viral term helped put a name to a change that internet users are noticing: the feeling that many of your digital experiences, transactions, and services are not improving with time, but are actually becoming worse because of their makers' updates.

Enshittification, according to Mr. Doctorow, is a way of naming the process through which internet platforms are being made deliberately worse for customers, by their decision-makers, until they decay completely. "Here is how platforms die: first, they are good to their users; then they abuse their users to make things better for their business customers; finally, they abuse those business customers to claw back all the value for themselves. Then, they die," wrote Mr. Doctorow in 2023.

Enshittification is also used to refer to a range of symptoms that degrade your experience as an internet user or customer. Some examples include the insertion of advertisements, self-preferencing by tech companies, unfair bias in search results, once free features becoming paid, genuine products being replaced with lower-value dupes, and more. Mr. Doctorow also points out how apps offer massive potential for enshittification, because app users often have less freedom to block ads when compared to users who are accessing the same platform via the web.

Why does enshittification matter?

Last year, in his Marshall McLuhan lecture at the Transmediale festival in Berlin, Mr. Doctorow pointed to four factors that could either constrain or enable the enshittification of platforms, based on how strong they are. These factors were – competition, regulation, self-help measures by users, and the unionisation of tech workers. When these four factors are strengthened, according to Mr. Doctorow, internet platforms are forced to become better for users. When weakened, however, customers are more vulnerable to being exploited by tech giants. In other words, when your experience with a shopping app or a streaming platform grows worse, much of this enshittification can be traced back to the dominance of just a few Big Tech players, looser antitrust enforcement by authorities, customers' diminished capacity to control their digital experiences, and/or the inability of tech workers to say no to exploitative bosses, according to the author.

How have social media companies changed their user experience?

Meta-owned Facebook is an example that Mr. Doctorow frequently cites to demonstrate enshittification. Originally meant to serve users and help them stay connected, Facebook users are now "locked in" along with advertisers and publishers, according to him, meaning that content from these latter two groups now take precedence over less profitable posts, such as content from friends and those you are following.

Instagram is yet another example of this enshittification, with advertisements and recommended content now often crowding out updates from those you actually care about – without your consent. Now, with AI-powered accounts joining the fray, human users compete for attention with non-human accounts.

Switching platforms becomes difficult because a large number of people need to depart at once in order for the move to be effective, but it can happen. "All it takes is one Cambridge Analytica scandal, one whistleblower, one livestreamed mass-shooting, and users bolt for the exits, and then FB discovers that network effects are a double-edged sword," noted Mr. Doctorow in his 2024 speech.

Enshittification can also be seen with X (formerly Twitter) after Elon Musk's takeover. Once a platform where verified world leaders, journalists, celebrities, and other noteworthy figures could connect with audiences, Twitter under Mr. Musk soon made its free blue tick verification a paid feature that could be bought by anyone ranging from neo-Nazis to scam bots in order to boost their presence.

degrading the platform experience for everyone. Dating apps such as Bumble and Hinge have also been accused of becoming "enshittified," with certain profile selections, profile exposure, profile filters, and viewing features being put behind paywalls, in order to encourage subscriptions. For instance, the feature to undo a mistaken 'swipe left' gesture that rejects a profile is a paid privilege on Bumble.

Enshittification could further explain the recent changes made to browsers like Google, which has applied its Generative AI-powered overviews into the search experience, so that users are first shown a mashup of search results pulled from random sources across the web, with more errors likely to appear. This also preferences Google as opposed to other, more authoritative news sources and/or smaller publishers.

How have streaming and entertainment platforms changed?

Amazon Prime, Netflix, YouTube, and Spotify are all examples of how enshittification can affect even daily activities such as watching your favourite TV show or listening to music. Rising subscription prices have nudged users to either pay more in order to again access to the ad-free content they were enjoying at lower prices, or be forced to watch ads.

YouTube, for example, has degraded its free experience with multiple unskippable ads even as it tries to push users to opt for its ad-free YouTube Premium subscription service. YouTube has also worked to obstruct the user experience of those who rely on external ad-blocking extensions in order to continue watching videos without forced commercial breaks. The company further announced a 'Hype' feature in certain countries that allows users to help boost creators in the YouTube Partner Program (those with 500 to 5,00,000 subscribers) and increase their exposure; this leads to users being shown fan-promoted content.

Meanwhile, users have taken to social media to complain how the free version of Spotify is close to unusable, with non-paying users unable to even have control over the order in which they listen to their chosen songs. This dissatisfying experience pushes people to opt for a paid subscription or forces them to find an alternative. Mr. Doctorow further alleged that Spotify replaces the ambient artists in its most popular playlists with soundalikes who aren't entitled to royalties.

How have e-commerce platforms changed?

In a 2022 blog post, Doctorow used the case of e-commerce giant Amazon to give an example of enshittification, noting that "Amazon is an enshittified endless scroll of paid results, where winning depends on ad budgets, not quality."

Mr. Doctorow went on to highlight how both sponsored product listings as well as Amazon's own products often take precedence while a user is searching for items, meaning that they are not necessarily being shown the best products first. Google, Apple, and Spotify have also been accused of this kind of self-preferencing, where content that is more profitable to the companies is shown first, to the loss of other business rivals.

Meanwhile, the difficulty of cancelling an Amazon Prime account has become a legal challenge in itself. Per a U.S. Federal Trade Commission (FTC) lawsuit, Amazon allegedly enrolled millions of customers in Amazon Prime subscriptions without their consent, and also complicated the cancellation process.

The e-commerce giant will have to pay $2.5 billion to settle the case – a slap on the wrist for a company with a market cap of over $2 trillion.

2. डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर अभिव्यक्तियाँ

- सोशल मीडिया:
  - फेसबुक और इंस्टाग्राम: एक समय उपयोगकर्ता-केंद्रित, अब विज्ञापनों, प्रभावशाली विपणन और एआई-जनित या अनुशंसित सामग्री का वर्चस्व है जो जैविक पहुंच को कम करती है।
  - Twitter (अब X): Elon Musk के तहत सत्यापन और पहुंच से कमाई हुई, जिससे गलत सूचना और घोटाले का प्रसार हुआ.
  - डेटिंग ऐप्स (Bumble, Hinge): पेवॉल के पीछे बंद स्वाइप या प्रोफ़ाइल दृश्यता को पूर्ववत करने जैसे बुनियादी कार्य।
- स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म:
  - यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई: बढ़ती सदस्यता शुल्क, दखल देने वाले विज्ञापन और प्रतिबंधित मुफ्त संस्करण। सामग्री पर उपयोगकर्ताओं का नियंत्रण तेजी से सीमित होता जा रहा है।
  - Amazon Prime: ऐड-सपोर्टेड प्लान और ऑटोमैटिक एनरोलमेंट विवाद शोषक मॉनेटाइज़ेशन का उदाहरण देते हैं.
- ई-कॉमर्स और सर्च इंजन:

- Amazon: खोज परिणाम उपयोगकर्ता मूल्य के बजाय प्रायोजित लिस्टिंग और Amazon के स्वयं के उत्पादों को प्राथमिकता देते हैं.
- Google: AI-जनित अवलोकन और स्व-वरीयता प्रामाणिक खोज परिणामों को विकृत करते हैं और छोटे प्रकाशकों को कमजोर करते हैं।

3. Enshittification के कारण और प्रवर्तक

डॉक्टरो चार प्रमुख कारकों की पहचान करता है जो यह निर्धारित करता है कि प्लेटफ़ॉर्म शोषक बन जाते हैं या नहीं:

एक. प्रतिस्पर्धा: कम बाजार प्रतिस्पर्धा एकाधिकार को हावी होने की अनुमति देती है।
दो. विनियमन: कमजोर अविश्वास प्रवर्तन उपभोक्ता विरोधी प्रथाओं को सक्षम बनाता है।
तीन. उपयोगकर्ता स्व-सहायता: "लॉक-इन प्रभाव" के कारण विज्ञापनों को ब्लॉक करने या प्लेटफ़ॉर्म बदलने की सीमित उपयोगकर्ता क्षमता।
चार. श्रमिक संघीकरण: अनैतिक कॉर्पोरेट नीतियों का विरोध करने में तकनीकी श्रमिकों की असमर्थता।

जब ये सुरक्षा उपाय कमजोर हो जाते हैं, तो प्लेटफ़ॉर्म उपयोगकर्ताओं का अधिक आक्रामक तरीके से शोषण करते हैं, जिससे डिजिटल विश्वास और अनुभव कम हो जाता है।

4. व्यापक निहितार्थ

- आर्थिक: बिग टेक खिलाड़ियों के बीच बाजार की शक्ति का एकाग्रता नवाचार को दबाता है और छोटे व्यवसायों को नुकसान पहुंचाता है।
- सामाजिक: उपयोगकर्ता की निराशा, गलत सूचना और ऑनलाइन इंटरैक्शन की प्रामाणिकता में कमी।
- नैतिक: डिजिटल स्वायत्तता, गोपनीयता और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा के प्रश्न।
- नीति: मजबूत डिजिटल शासन, उपभोक्ता संरक्षण और अविश्वास प्रवर्तन की आवश्यकता है।

निष्कर्ष

डिजिटल प्लेटफार्मों का उत्साहीकरण उपयोगकर्ता-केंद्रित से लाभ-केंद्रित डिजाइन की ओर एक जानबूझकर बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है - एकाधिकार शक्ति और कमजोर विनियमन द्वारा संचालित कॉर्पोरेट क्षय का एक रूप। जबकि उपयोगकर्ता शक्तिहीन महसूस कर सकते हैं, प्रक्रिया अपरिवर्तनीय नहीं है। प्रतिस्पर्धा कानूनों को मजबूत करना, डिजिटल साक्षरता बढ़ाना, प्लेटफ़ॉर्म जवाबदेही को प्रोत्साहित करना और नैतिक तकनीकी विकास का समर्थन करना इंटरनेट के मूल वादे को बहाल करने में मदद कर सकता है - खुलेपन, नवाचार और उपयोगकर्ता सशक्तिकरण के लिए बनाया गया स्थान।

NITIN SIR CLASSES

THE HINDU

INDIA'S NATIONAL NEWSPAPER SINCE 1878

UPSC Prelims Practice Question
प्रश्न : हाल ही में समाचारों में देखे गए "एनशिटिफिकेशन" शब्द के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. यह उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसके द्वारा लाभ-अधिकतम निर्णयों के कारण डिजिटल प्लेटफॉर्म धीरे-धीरे गुणवत्ता में खराब हो जाते हैं।
2. यह शब्द एलोन मस्क द्वारा 2020 के बाद सोशल मीडिया में बदलाव का वर्णन करने के लिए गढ़ा गया था।
3. Enshittification मुख्य रूप से कमजोर प्रतिस्पर्धा, विनियमन और उपयोगकर्ता नियंत्रण के कारण होता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1
(b) केवल 1 और 3
(c) केवल 2 और 3
(d) 1, 2 और 3
उत्तर: (b)
UPSC Mains Practice Question
प्रश्न: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के क्षरण को रोकने में प्रतिस्पर्धा, विनियमन और उपयोगकर्ता सशक्तिकरण की भूमिका पर चर्चा करें। भारत नैतिक और उपयोगकर्ता-केंद्रित डिजिटल प्लेटफॉर्म कैसे सुनिश्चित कर सकता है? **(150 शब्द)**

□□□□□ □□□□□□□

Page 13 : GS 1 : Social Issues / Prelims

पारंपरिक रूप से पुरुष-प्रधान समुद्री क्षेत्र में एक उल्लेखनीय परिवर्तन देखा जा रहा है और भारतीय महिलाएं तेजी से समुद्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। मुंबई में आयोजित इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 ने कैप्टन राधिका मेनन, सुनीता बाला और रेशमा नीलोफर विशालाक्षी जैसी अग्रणी महिला नाविकों को सम्मानित करके इस बदलाव का जश्न मनाया, जो सबसे कठिन व्यवसायों में से एक में बाधाओं को तोड़ने की प्रतीक हैं।

प्रमुख विकास और डेटा

जहाजरानी महानिदेशालय के अनुसार, भारतीय महिला नाविकों की संख्या 2021 में 1,600 से बढ़कर 2024 के अंत तक लगभग 6,000 हो गई – जो लगभग चार गुना वृद्धि है। यह वृद्धि लैंगिक समावेशिता के उद्देश्य से सरकारी पहलों और निजी क्षेत्र के प्रयासों दोनों को दर्शाती है।

- तकनीकी समावेशन: इलेक्ट्रो टेक्निकल कैडेट और ट्रेनी इंजन रेटिंग जैसी तकनीकी भूमिकाओं में महिलाओं की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है, जो तकनीकी पदों की मांग में महिलाओं की अधिक स्वीकार्यता को दर्शाता है।
- संस्थागत समर्थन:
  - सरकारी हस्तक्षेपों ने जागरूकता पैदा की है और बेहतर अवसर सुनिश्चित किए हैं।
  - मार्सक के "इक्वल एट सी" (2022) जैसे निजी क्षेत्र के कार्यक्रम जहाजों पर विविधता, समावेशन और सुरक्षित कार्य वातावरण पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
- रोल मॉडल: कैप्टन राधिका मेनन (भारत की पहली महिला कप्तान) और रेशमा निलोफर विशालाक्षी (भारत की एकमात्र समुद्री पायलट) जैसे ट्रेलब्लेज़र युवा महिलाओं के लिए समुद्री करियर में शामिल होने के लिए प्रेरणा के रूप में काम करते हैं।

सकारात्मक प्रवृत्ति के कारण

एक. जागरूकता और आउटरीच: महिलाओं के लिए एक व्यवहार्य करियर विकल्प के रूप में समुद्री यात्रा की समझ में वृद्धि।
दो. नीति समर्थन: छात्रवृत्ति, शुल्क रियायतें और अनुकूल ऑनबोर्ड नीतियां।
तीन. कॉर्पोरेट पहल: विविधता और सुरक्षित कार्य वातावरण पर उद्योग-व्यापी ध्यान।
चार. सांस्कृतिक बदलाव: तकनीकी और नेतृत्व की स्थिति में महिलाओं की भूमिकाओं के बारे में धारणाओं को बदलना।

भारत के लिए महत्व

- आर्थिक सशक्तिकरण: समुद्री कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी का विस्तार समावेशिता और उत्पादकता को बढ़ावा देता है।
- वैश्विक प्रतिनिधित्व: कुशल समुद्री पेशेवरों के आपूर्तिकर्ता के रूप में भारत की प्रतिष्ठा को मजबूत करता है।
- सामाजिक प्रभाव: विमानन, रक्षा और रसद जैसे अन्य पुरुष-प्रधान क्षेत्रों में लैंगिक समानता के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है।

Growing Indian women power on global ships

Ruling the sea: The number of women in technical roles such as Electro Technical Cadet saw consistent growth.

T. E. Raja Simhan

Meet these illustrious Indian women seafarers. Suneeti Bala, first Indian women to serve as chief engineer of a merchant vessel; Reshma Nilofer Visalakshi, India's only marine pilot, currently steering ships from sea to Kolkata and Haldia port; Sonali Banerjee, India's first lady marine engineer; Parvathy Ralakshmi, a naval architect and Capt. Radhika Menon of Captain Synergy Ship Management.

At last week's India Maritime Week 2025 held in Mumbai, these women seafarers were felicitated for being leading industry torch bearers to woo budding talent, and help in increase the number of Indian women seafarers.

According to data by the Directorate General of Shipping, In 2021, there were 1,600 Indian women seafarers globally. This number increased to nearly 6,000 by the end of 2024. This has been due to many like Centre's intervention to ensure that more women join the maritime industry, awareness and global shipping lines' diversity on board the ships.

Positive trend

Data from 2021 to 2024 indicates a positive trend in the inclusion of female ratings and officers within both nautical and engineering departments. Notably, the number of women in technical roles such as Electro Technical Cadet and Trainee Engine Rating has seen consistent growth, reflecting the increasing openness of the maritime sector to female professionals, says Directorate General of Shipping, which manages Indian seafarers globally.

On the increase in the number of women seafarers, Capt. Radhika Menon, says the reasons include awareness regarding the profession of seafarers among women, role model pioneers, support from industry and regulatory bodies, policies for promotion of conducive atmosphere for women on board, scholarships and concessions in fees.

According to Karan Kochhar, MD, Maersk Fleet Management & Technology India & Head of Marine People Asia, A.P. Moller - Maersk, the rise in the number of women seafarers can be attributed to a combination of factors. These include greater industry-wide focus on diversity and inclusion, proactive government initiatives supporting women, growing awareness of maritime careers among women, and improved shipboard policies that ensure safer and more supportive working environments.

Maersk launched the 'Equal At Sea' initiative in 2022 which saw remarkable success with it in India. The programme's main aim is to achieve greater diversity among Maersk seafarers, tackle the historical under-representation of women among seafarers and foster an ecosystem across the Indian maritime sector to improve gender diversity. The programme unites industry stakeholders on a common platform, acting as a hub for exchanging ideas and adopting best practices, among other things, Mr. Kochhar said.

(The writer is with The Hindu businessline)

निष्कर्ष

भारतीय महिला नाविकों की लगातार वृद्धि वैश्विक शिपिंग में लैंगिक समानता की दिशा में एक शक्तिशाली कदम का प्रतीक है। सरकारी नीतियों, निजी पहलों और प्रेरक रोल मॉडल द्वारा समर्थित, समुद्री क्षेत्र एक अधिक समावेशी क्षेत्र में विकसित हो रहा है। जैसा कि कैप्टन राधिका मेनन और अन्य लोग प्रेरित करना जारी रखते हैं, समुद्र में भारत की बढ़ती महिला शक्ति सशक्तिकरण और उत्कृष्टता दोनों के प्रमाण के रूप में खड़ी है - जो राष्ट्र को सभी क्षितिज पर समान विकास की ओर ले जा रही है।

UPSC Prelims Practice Question

प्रश् न : भारत में समुद्री क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. 2021 और 2024 के बीच भारतीय महिला नाविकों की संख्या में लगभग चार गुना वृद्धि हुई है।

2. नाविकों के बीच लैंगिक विविधता को बढ़ावा देने के लिए मार्सक की 'इक्वल एट सी' पहल शुरू की गई थी।

3. जहाजरानी महानिदेशालय वैश्विक स्तर पर भारतीय नाविकों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है?

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3

(d) 1, 2 और 3

उत्तर: d)

UPSC Mains Practice Question

प्रश्न: वैश्विक शिपिंग में भारतीय महिलाओं की बढ़ती भागीदारी समावेशिता और सशक्तिकरण के एक नए युग का प्रतीक है। **(150 शब्द)**

□□□□□ □□□□□□□

Page : 08 Editorial Analysis

The vision of Model Youth Gram Sabhas

In India's democratic architecture, the Gram Sabha holds a significance that is as fundamental as that of the Lok Sabha or Vidhan Sabha. Yet, the Gram Sabha, the constitutional cornerstone of grassroots democracy, remains an unsung hero in popular conversations and civic awareness. Unlike the Bal Sansad (Children's Parliament), Youth Parliament, and the Model United Nations, the Model Youth Gram Sabha is an unfamiliar concept for most. Yet, it is in these village assemblies, not the grand chambers of Parliament, that democracy finds its purest expression – direct, participatory, and accountable.

Article 243A of the Constitution, introduced by the 73rd Amendment Act of 1992, defines the Gram Sabha as the foundation of the Panchayati Raj system. It represents every registered voter in a village and empowers them to deliberate on budgets, development plans, and governance priorities. This institution embodies participatory democracy, empowering rural citizens to shape decisions affecting their community, fostering transparency, accountability, and inclusive development. But despite its revolutionary potential, participation remains minimal.

Sushil Kumar Lohani

A 1995 batch IAS officer of the Odisha cadre and currently Additional Secretary in Ministry of Panchayati Raj, Government of India. Email: s.lohani@nic.in

Manmohan Singh

CEO-Aspirational Bharat Collaborative, Piramal Foundation. Email: manmohan@gandhifellow-ship.org

If the Model United Nations cultivates global citizenship, the Model Youth Gram Sabha can nurture civic pride and local leadership

Why aren't Gram Sabhas aspirational?

Ask any young person if they dream of leading a village or becoming a Sarpanch, and you will likely be met with a puzzled silence. The educational curriculum largely focuses on Lok Sabha and Vidhan Sabha elections, parliamentary governance, or global models such as the United Nations. It remains silent on the Panchayati Raj institutions that form the bedrock of Indian democracy. This absence from classrooms has turned the Gram Sabha into a distant administrative concept rather than a living democratic experience. To build a 'Viksit Bharat', the Gram Sabha must be positioned as aspirational, empowering rural youth, women, farmers to lead at the grassroots, shaping development and democracy. This requires embedding Gram Sabha simulations into school and college curriculum.

It was to bridge this gap that the Ministry of Panchayati Raj, in collaboration with the Ministry of Education, Ministry of Tribal Welfare and the Aspirational Bharat Collaborative, launched the Model Youth Gram Sabha in 2025. Simulating real Gram Sabha processes, students play the roles of Sarpanch, ward members, health workers, and engineers discussing village budgets and development plans. The programme is supported by teacher training and offers incentives such as prizes and certificates to encourage enthusiastic participation. The exercise transforms abstract civics into lived experience, cultivating local governance knowledge, and making democratic participation concrete and engaging for the future generation.

In Phase 1, the Model Youth Gram Sabha is being launched in over 1,000 schools across 28 States and eight Union Territories (UTs). These include more than 600 Jawahar Navodaya Vidyalayas, 200 Eklavya Model Residential Schools, and select Zilla Parishad schools in Maharashtra. A team of 126 master trainers is leading nationwide teacher training. So far, 1,238 teachers from 24 States and UTs have been trained. More sessions are in progress.

Prior to the national rollout, successful pilots were held at Jawahar Navodaya Vidyalaya Baghpat in Uttar Pradesh and Eklavya Model Residential School Alwar in Rajasthan. The Jawahar Navodaya Vidyalaya, Sitapur, in Bundi district, Rajasthan, became a living classroom of democracy as more than 300 students participated in a Model Youth Gram Sabha. In Phase 2, the initiative intends to expand beyond central institutions and Zilla Parishad schools to include all State-run schools across India.

From simulation to transformation

In a democracy such as India, active citizen participation is not just a right but a responsibility. If the Model United Nations cultivates global citizenship, the Model Youth Gram Sabha can nurture civic pride and local leadership. By being introduced to the Panchayati Raj systems, students are better able to understand the rights and responsibilities of citizens in a democratic setup. The experience of conducting debates, passing resolutions, and negotiating consensus instils critical life skills.

This model has the potential to redefine civic education. By expanding it to all schools and colleges, India can make participation aspirational again. A future IAS officer or parliamentarian who once "chaired" a Youth Gram Sabha in school is more likely to value the power of local governance in real life.

The vision of Viksit Bharat cannot rest on policy alone. It depends on citizens who see governance not only as the government's responsibility but as a shared civic duty. The Model Youth Gram Sabha is more than a classroom exercise; it is a seedbed for democratic renewal.

When young people learn that their village meeting is as vital as Parliament, democracy ceases to be an abstract system – it becomes a lived culture. And when every child in India grows up believing their voice matters at the Gram Sabha, the dream of a truly participatory, self-reliant, and compassionate nation will no longer be a distant aspiration. It will be the everyday rhythm of Indian democracy.

GS. Paper 2 □□□□□□□ □□□□□□□□

UPSC Mains Practice Question: □□□□ □□□ □□□□□□ □□□□ पर □□□□□□□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□ पहल □□ □□□□□□ पर □□□□□□ □□□□□□ (150 □□□□□)

□□□□□ □□□□□□□

संदर्भ:

73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के माध्यम से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243ए के तहत परिकल्पित ग्राम सभा, पंचायती राज प्रणाली की नींव बनाती है और भारत में सहभागी लोकतंत्र के सार का प्रतिनिधित्व करती है। हालाँकि, जमीनी स्तर पर शासन का आधार होने के बावजूद, इसकी कम सराहना की गई है और इसका कम उपयोग किया गया है।

इस अंतर को दूर करने के लिए, पंचायती राज मंत्रालय ने शिक्षा और जनजातीय मामलों के मंत्रालयों के सहयोग से 2025 में मॉडल युवा ग्राम सभा (MYGS) पहल शुरू की । इस पहल का उद्देश्य शैक्षणिक संस्थानों के भीतर ग्राम सभा की कार्यवाही का अनुकरण करके नागरिक भागीदारी को पुनर्जीवित करना और युवाओं के बीच लोकतांत्रिक मूल्यों को स्थापित करना है।

भारतीय लोकतंत्र में ग्राम सभा का महत्व

- संवैधानिक जनादेश: अनुच्छेद 243A ग्राम सभा को बजट, विकास योजनाओं और स्थानीय शासन प्राथमिकताओं पर विचार-विमर्श करने का अधिकार देता है।
- सहभागी लोकतंत्र की नींव: यह नागरिकों को निर्णय लेने में सीधे भाग लेने, शासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और समावेशिता को बढ़ावा देने की अनुमति देता है ।
- विकसित भारत से जुड़ाव: विकसित भारत (विकसित भारत) को साकार करने के लिए न केवल नीतिगत सुधारों की आवश्यकता है, बल्कि जमीनी स्तर पर सक्रिय नागरिक जुड़ाव की भी आवश्यकता है।

समस्या: ग्राम सभाएं आकांक्षात्मक क्यों नहीं हैं

एक. नागरिक जागरूकता का अभाव: स्कूल और कॉलेज मुख्य रूप से लोकसभा, राज्यसभा और संयुक्त राष्ट्र जैसी राष्ट्रीय और वैश्विक शासन संरचनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि स्थानीय स्व-सरकारी संस्थान पाठ्यक्रम में उपेक्षित रहते हैं ।

दो. सांस्कृतिक धारणा: युवा लोग शायद ही कभी ग्राम स्तर पर नेतृत्व को देखते हैं - जैसे कि सरपंच या वार्ड सदस्य बनना - महत्वाकांक्षी के रूप में। यह युवाओं और स्थानीय शासन के बीच लोकतांत्रिक संबंध को कमजोर करता है।

तीन. सीमित भागीदारी: अपनी क्षमता के बावजूद, ग्राम सभाओं में अक्सर खराब उपस्थिति और कमजोर विचारशील संस्कृति देखी जाती है, जो सहभागी शासन की भावना को कमजोर करती है।

पहल: मॉडल युवा ग्राम सभा (2025)

उद्देश्य:

स्कूलों और कॉलेजों में ग्राम सभा सिमुलेशन शुरू करके लोकतंत्र को अनुभवात्मक बनाना , जिससे युवाओं को जमीनी स्तर पर शासन से जोड़ा जा सके।

कार्यान्वयन की मुख्य विशेषताएं:

- सहयोग: पंचायती राज मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय और आकांक्षी भारत सहयोगी।
- चरण 1 कवरेज:
    - 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में 1,000 से अधिक स्कूल।

- इसमें 600+ जवाहर नवोदय विद्यालय, 200 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय और चुनिंदा जिला परिषद स्कूल शामिल हैं।

- **क्षमता निर्माण:**
  - 126 मास्टर प्रशिक्षक राष्ट्रव्यापी शिक्षक प्रशिक्षण का नेतृत्व कर रहे हैं।
  - अब तक 24 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 1,238 शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया है।
- शैक्षणिक दृष्टिकोण: छात्र वास्तविक ग्राम सभा प्रक्रियाओं का अनुकरण करते हैं - सरपंच, वार्ड सदस्यों, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, या इंजीनियरों जैसी भूमिकाएं निभाते हैं, बजट, स्थानीय योजनाओं और शासन के मुद्दों पर चर्चा करते हैं।
- प्रोत्साहन:
  छात्रों के बीच भागीदारी और उत्साह को प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कार और प्रमाण पत्र।

पायलट की सफलता:

- जवाहर नवोदय विद्यालय, बागपत (उत्तर प्रदेश) और एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, अलवर (राजस्थान) ने मजबूत जुड़ाव का प्रदर्शन किया।
- सीतापुर, बूंदी (राजस्थान) में 300 से अधिक छात्रों ने भाग लिया, जिससे कक्षाओं को लोकतंत्र की जीवित प्रयोगशालाओं में बदल दिया गया।

विश्लेषणात्मक परिप्रेक्ष्य: सिमुलेशन से परिवर्तन तक

एक. व्यवहार में लोकतांत्रिक शिक्षा: यह पहल अमूर्त नागरिक शास्त्र को अनुभवात्मक शिक्षा में बदल देती है, जिससे छात्रों को अधिकारों, जिम्मेदारियों और विचारशील निर्णय लेने को समझने में मदद मिलती है।
दो. स्थानीय नेतृत्व का पोषण: जिस तरह मॉडल संयुक्त राष्ट्र (MUN) वैश्विक नागरिकता को बढ़ावा देता है, उसी तरह मॉडल युवा ग्राम सभा जमीनी स्तर पर नेतृत्व और नागरिक गौरव को बढ़ावा देती है।
तीन. शासन की खाई को पाटना: यह शहरी और ग्रामीण छात्रों को समान रूप से इस बात की सराहना करने में मदद करता है कि प्रभावी शासन स्थानीय रूप से शुरू होता है, जिससे ग्राम सभाओं में भागीदारी सार्थक और आकांक्षात्मक दोनों हो जाती है।
चार. लोकतांत्रिक नवीनीकरण के लिए क्षमता: जो छात्र इस प्रक्रिया का अनुभव करते हैं, वे जिम्मेदार नागरिक, पंचायत सदस्य, नौकरशाह या राजनेता बनने की संभावना रखते हैं जो स्थानीय स्वशासन को महत्व देते हैं।
पाँच. दीर्घकालिक प्रभाव: शिक्षा में ग्राम सभा की अवधारणा को शामिल करने से नागरिक संस्कृति को नया आकार मिल सकता है, जिससे भागीदारी केवल एक अधिकार के बजाय एक साझा जिम्मेदारी बन जाएगी।

आगे की चुनौतियाँ

- स्केलिंग अप: सभी राज्यों और स्कूलों में एक समान कार्यान्वयन सुनिश्चित करना।
- शिक्षक की तैयारी: प्रभावी सिमुलेशन के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण और प्रेरणा आवश्यक है।
- मूल्यांकन तंत्र: प्रभाव को मापने के लिए मजबूत निगरानी और प्रतिक्रिया प्रणाली की आवश्यकता है।
- सांस्कृतिक परिवर्तन: सामाजिक पूर्वाग्रहों पर काबू पाना जो संसदीय राजनीति की तुलना में पंचायती नेतृत्व को कम आंकते हैं।

निष्कर्ष

□□□□□ □□□□□□

मॉडल युवा ग्राम सभा पहल शिक्षा में सहभागी लोकतंत्र को शामिल करने की दिशा में एक परिवर्तनकारी कदम है। छात्रों को शासन का प्रत्यक्ष अनुभव करने के लिए सशक्त बनाकर, यह लोकतांत्रिक आदर्शों और जीवित वास्तविकता के बीच की खाई को पाटता है। यदि प्रभावी ढंग से बढ़ाया जाता है, तो यह एक ऐसी पीढ़ी को विकसित कर सकता है जो न केवल जिम्मेदारी से वोट देती है, बल्कि स्थानीय शासन में भी सक्रिय रूप से भाग लेती है, लोकतंत्र को एक दूर की राजनीतिक प्रक्रिया के बजाय एक साझा नागरिक कर्तव्य के रूप में देखती है।

जैसा कि सुशील कुमार लोहानी ने ठीक ही कहा है, जब भारत का हर बच्चा ग्राम सभा में अपनी आवाज को मायने रखता है, तो लोकतंत्र एक व्यवस्था नहीं रह जाएगी - यह एक संस्कृति बन जाएगी। जमीनी स्तर के सशक्तिकरण में निहित यह दृष्टिकोण वास्तव में विकसित भारत की भावना और ग्राम स्वराज के गांधीवादी आदर्श के साथ मेल खाता है।